एमसीएफ़, 'हूडा' के साथ-साथ अब स्मार्ट सिटी लिमिटेड व एफ़एमडीए को भी ढोना पड़ेगा

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरामखोरी व रिश्वतखोरी बंद करने के अलावा बाकी सारे काम करेगी खट्टर सरकार। शहर की जो जनता पहले से ही नगर निगम व 'हूडा' के भ्रष्टाचार और निकम्मेपन को ढो रही है, उसे अब एक नई कम्पनी 'स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा एफ़एमडीए (फ़रीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवेलपमेंट आथॉरिटी) की हरामखोरी व व रिश्वतखोरी को भी ढोना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च के नाम पर जनता का जो पैसा लुटाया जायेगा वह अलग से।

जानकारों के मुताबिक स्मार्ट सिटी लिमिटेड तो शहर को स्मार्ट बनाने के लिये आवश्यक काम करेगी ही एफ़एमडीए इसे सहयोग देते हुये मास्टर रोड, मास्टर सीवर लाइन यानी तमाम बाहरी सेवायें प्रदान करेगी। दूसरे शब्दों में विभिन्न कॉलोनाइज़रों से जो ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) वसूला जाता है, उसे खर्च करके बाहरी विकास कार्य करेगी। विदित है कि नहर पार बस रहे ग्रेटर फ़रीदाबाद के बिल्डरों से सरकार दसियों हज़ार करोड़ वसूल कर डकार चुकी है जिसके बदले हुए विकास कार्य आज भी आधे-अधूरे पड़े हुए हैं।

'हूडा' भी एक कॉलोनाइज़र है, सरकारी ही सही। जानकारों के मुताबिक अब तक इडीसी के पैसा 'हूडा' के माध्यम से ही खर्च किया जाता था परन्तु अब यह काम एफ़एमडीए के माध्यम से कराया जायेगा। यानी इस धंधे में जो माल-मलाई व लूट कमाई 'हूडा' कर्मचारियों को होती थी वह बंद हो जायेगी। इसकी सुगबुगाहट भर से सम्बन्धित 'हूडा' कर्मचारियों में बेचैनी नज़र आने लगी है। इसको लेकर उनके बयान भी अखबारों में आने लगे हैं। यद्यपि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटाने की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं है। लेकिन खाली नौकरी से तो पेट नहीं भरता मलाई खाने वालों का। कुछ ऐसी ही स्थिति नगर निगम वालों की भी है।

सरकार की इस जनविरोधी नीति एवं योजना का दुष्परिणाम यह होगा कि शहर की दुर्दशा यानी जल भराव, सीवर जाम व सड़कों में गड्ढों के लिये कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगा, सभी एक दूसरे पर दोष मंढते रहेंगे। इसका बेहतरीन उदाहरण दिल्ली में देखा जा रहा है। वहां नगर निगम, पीडब्लूडी, सीपीडब्लूडी, डीडीए, दिल्ली व केन्द्र सरकार सदैव एक दूसरे पर दोष मंढने पर लगे रहते हैं और जनता भुगतती रहती है।

गैंगरेप : त्वरित कार्यवाही का बेहतरीन नमूना.....

पेज एक का शेष

वारदात भी कर लेते थे। इस तरह की वारदातों में वे पहले पकड़े भी जा चुके हैं। एक मूर्खता तो वे इस वारदात के दौरान भी करते-करते रह गये। वारदात के दौरान इन्होंने पीड़िता के मित्र को घर से 30 000 रुपये लाने के लिये भी कहा था, लेकिन ऐन वक्त पर इरादा बदल दिया, वरना तो ये उसी वक्त धर-दबोचे जाते।

शुक्रवार को नीमका जेल में हुई शिनाख्त परेड के दौरान पीड़िता को चारों अपराधियों को पहचानने में कतई कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसने दियासलाई व मोबाइल की रोशनी में उनकी शक्ल इतनी अच्छी तरह से पहचान ली थी कि उसी के आधार पर पुलिस ने उन्हें पिन-प्वायंट किया था।

चौथे अपराधी ने भागने के प्रयास में टांग तुड़वाई

पुलिस ने हर तरफ़ से पुष्टि कर लेने व पक्का यकीन होने के बाद चारों अपराधियों के घरों को बहुत ही गुप्त ढंग से रात भर घेरे रखा। सुबह करीब साढ़े तीन बजे एक साथ चारों घरों में पुलिस घुसी। तीन तो तुरंत दबोच लिये गये लेकिन चौथे ने पहली मंजिल से छलांग मार कर अपनी एक टांग तुड़वा ली। लेकिन दहशत बड़ी चीज़ होती है। इसके आगे टूटी टांग का दर्द भी कहीं नहीं ठहर पाया। लिहाज़ा वह ऐसा भागा कि दोपहर बाद कहीं जाकर उसे पुनहाना के इलाके से पकड़ा जा सका।

अब पुलिस की कोशिश है कि जितने रिकॉर्ड टाइम में अपराधियों को धर-दबोचा गया है उसी तर्ज पर चालान कोर्ट में भेज कर सभी अपराधियों को रिकॉर्ड समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने के बारे सोचने से भी लोग घबरायें।

इस केस से सिद्ध होता है कि पुलिस करने पर आये, बशर्ते कि उसे करने दिया जाय, वांछित संसाधन एवं मार्ग दर्शक उपलब्ध कराया जाय तो कोई काम मुश्किल नहीं।

आगरा नहर पर गश्त बढाई जाय

अपराध होने के बाद की पुलिस कार्यवाही तो बेशक प्रशंसनीय है, परन्तु अपराध रोकने के लिए जो कुछ होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा। आगरा नहर की पूर्वी पटरी पर पक्की सड़क बनने व ग्रेटर फ़रीदाबाद के बसने से रात-बिरात लोगों का आना-जाना व घूमना फ़िरना लगा रहता है। गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात न सही लेकिन अनेकों वारदातें यहां काफ़ी अर्से से होती आ रही हैं। इन्हें देखते हुये पुलिस को यहां गश्त एवं चौकसी बढ़ानी चाहिये थी। लेकिन गश्त का अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि लाल-नीली बत्ती जला कर सायरेन बजाते हुये पुलिस वहां से गुजर जाय। अपराधियों को दबोचने के लिये पुलिस को घात लगा कर पकड़ने की रणनीति अपनानी होगी।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बैठक

मज़दूर मोर्चा के 16-22 सितम्बर 2018 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाचार प्रकाशित हुए हैं। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद लगभग साढे चार वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी द्वारा दिखाए गये सपने व वादे पूरे न होने तथा जनता की आशाओं व अपेक्षाओं पर पूरी न उतरने के कारण भाजपा सरकार की लोकप्रियता व विश्वसनीयता गिरती जा रही है। जैसे-जैसे पांच राज्यों की विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनाव निकट आ रहे हैं भाजपा की चिंतायें भी बढ़ती जा रही है।

हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने भी नई-नई योजनाओं की घोषणा तथा नींव-पत्थर लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब जनता को रिझाने के लिये हरियाणा में बिजली के 500 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को दामों में कुछ राहत देने की घोषणा की है जबकि बिजली की सप्लाई में कोई सुधार नहीं किया गया है। 'धरती लगे फ़टने तो खैरात लगी बंटने-चुनावी बेला में बिजली के दाम घटे, समय आने पर तेल के दाम भी घटेंगे' में हरियाणा में बिजली उत्पादन व बिजली के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में हो रही गड़बड़ी से पाठकों को रूबरू कराया गया है।

केन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद तथा केन्द्रीय मंत्री टीवी चैनलों पर कह रहे हैं कि तेल के बढते दाम सरकार के हाथ में नहीं है, जबकि कर्नाटक विधान सभा चुनाव के दौरान लगभग डेढ महीने तक केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर तेल के दाम नहीं बढ़े थे परंतु मतदान पूरा होते ही तेल के दाम बढने शुरू हो गये जो आज तक जारी है। तेल के दामों के कारण जनता के बढ़ते असंतोष को शांत करने के लिये मोदी सरकार लोक सभा चुनाव से पूर्व तेल के दामों में कटौती करेगी जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तथा योग गुरू व्यवसायी रामदेव के बयानों से स्पष्ट इंगित होता है।

केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गूजर ने प्रधानमंत्री मोदी के पदचिन्हों पर चलते हुये फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आम सभा में अपने साढे चार साल के शासन में इस शहर को विकसित कर देने का दाबा किया, परंतु उन्होंने क्या विकास किया यह नहीं बताया। हां, कई जगह पर नींव पत्थर जरूर रखे हैं, नारियल फ़ोड़े हैं और अखबारों में बयान व फ़ोटो छपवाये हैं, जिसका 'पिछली सरकार ने उजाड़ा, हमने बसाया- कृष्णपाल गूजर-नारियल फ़ोड़ने, झूठ बोलने में मोदी-शिष्य का कोई सानी नहीं है' में खुलासा किया है। मंत्रीजी का बहु प्रचारित निर्माणाधीन मंझावली यमुना पुल से नोयडा और फ़रीदाबाद को जोड़ने का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

'मोदी का 4 लाख करोड़ के नये एनपीए का तोहफ़ा देश को' में विद्युत उत्पादन क्षेत्र तथा आईएस एफ़एस समूह को दिये गये कर्जों का भुगतान सम्बन्धित बैंकों को न होने के कारण लगभग 4 लाख करोड़ के नए एनपीए घोटाले की विवेचना की गई है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को अब तक इनके विरुद्ध दिवालिया होने की कार्यबाई शुरू करनी थी, परंतु उसके बाद इन कर्जों को एनपीए दिखाना पड़ता जो नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस कार्यवाई को रोक दिया गया है। मोदी सरकार इस चार लाख करोड़ के कर्ज को एनपीए घोषित करने से लोकसभा चुनाव तक बचना चाहती है, क्योंकि एनपीए का बढ़ता संकट पूरी बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था में संकट को और गहरा करेगा तथा मोदी सरकार की विश्वसनीयता पर और आशंका बढेगी।

पिछले दिनों दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बैठक भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तथा अमरीकी विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री के बीच हुई । इस बैठक में भारत का मुख्य जोर दो मुद्दों पर था- पहला कि भारत ईरान से तेल मंगाता रहे तथा दूसरा रूस से एस 400 मिसाइल प्रणाली का सौदा जो आखिरी चरण में पूरा हो, परंतु अमेरिका ने इन दोनों मुद्दों को इग्नोर करते हुये कहा कि पहले बड़े और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि यह टू प्लस टू बैठक मुख्य रूप से रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली और ईरान से तेल खरीदने की भारत योजना पर केन्द्रित नहीं है। भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर रक्षात्मक समझौते के कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (कॉमकासा) पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसका 'मोदी सरकार ने देश की सम्प्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का पाप किया' में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है। यह कॉमकासा समझौता दोनों देशों के सैन्य बलों के संचार नैटवर्कों को आपस में जोड़ देगा और अमेरिका अपनी कम्पनियों द्वारा सप्लाई किये गये हथियारों का समय-समय पर निरीक्षण करने का हकदार होगा, जिससे भारत की कोई भी तकनीक गोपनीय नहीं रह पायेगी।

किंग किशर के मालिक विजय माल्या ने लंदन जाने से ठीक एक दिन पहले 01 मार्च 2016 को वित्तमंत्री अरूण जेटली से राज्य सभा में भेंट करते हुये बताया कि वह लंदन जा रहा है और बैंक से समझौता कर कर्ज की भुगतान करना चाहता है, जिसका 'खबर (दार)- झरोखा वित्त मंत्री अरूण जेटली को तत्काल इस्तीफ़ा देना चाहिये' में सटीक विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त सीबीआई ने अक्तूबर 2015 में माल्या के नाम लुकआउट नोटिस जारी किया था जिसे एक माह बाद नवम्बर में सीबीआई के जॉईन्ट डायरेक्टर ने यह कहते हुये वापिस ले लिया कि माल्या के खिलाफ़ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस प्रकरण से दो मुख्य प्रश्न खड़े होते हैं-पहला कि माल्या द्वारा लंदन जाने के बारे में बताने के बाद क्या वित्त मंत्री जेटली ने प्रधान मंत्री को इस मुलाकात के बारे में बताया तथा दूसरा कि सीबीआई के जॉईन्ट डायरेक्टर ने किसके निर्देश पर लुक आउट नोटिस को बदला। इस पूरे विवाद में मोदी तथा जेटली दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं।

यूपीए के शासन काल 2013-14 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था और तेल के दाम बढ़ रहे होते थे तब भाषण देने में माहिर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में यूपीए सरकार के खिलाफ़ दहाड़ा करते थे और लोग कहते थे कि हमें बोलने वाला नेता चाहिये जिससे उत्साहित होकर भाजपा के अन्य नेताओं ने भी बोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु अब प्रधानमंत्री के साढे चार साल के शासन काल में डॉलर के मुकाबले रुपया धराशायी होता जा रहा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया है, राफ़ेल डील पर मोदी जी की भूमिका विवादों के घेरे में है, लोगों के काम धंधे चौपट हो रहे हैं, परंतु बोलने वाले मोदी जी चुप्पी साधे हुये हैं, कुछ नहीं बोलते, जिसका 'बोलिये मादीजी, देश को बोलने वाला नेता चाहिये था... बोलिये न....' में विस्तृत चर्चा की गई है। वे केवल अपनी पार्टी संगठन की बैठक तथा जन सभाओं में ही बोलते हैं जहां कोई भी उनसे ऐसे प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर सकता, जिनसे उनको असहजता हो।

2014 में क्रूड तेल का दाम 107-09 डॉलर प्रति बैरल था तब भारत में पैट्रोल 70 रुपये तथा डीज़ल 55-00 रुपये प्रति लीटर बिकता था। अब सितम्बर 2018 में क्रूड तेल का दाम 73 डॉलर प्रति बैरल है। तब भी भारत में पैट्रोल 86-00 रुपये तथा डीजल 78-00 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यूपीए काल 2013-14 के मुकाबले में अब क्रूड तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के बावजूद मोदी सरकार एक्साइज़ डयूटी व वैट के जरिये जनता की जेब पर डाका डाल रही है, जिसका ''सरकार ने पिछले चार साल में तेल के ज़रिये आपका 'तेल' निकाल दिया है'' में पर्दाफ़ाश किया गया है।

मोदी सरकर के मन्त्रियों द्वारा तेल की कीमत उनके हाथ में न होने के बयान देने तथा पैट्रोल पम्प पर मोदी के फ़ोटो वाले होर्डिंग लगाने पर 'जब तुम्हारे हाथ में तेल की कीमत ही नहीं है, तो क्या पैट्रोल पंपों पर फ़ोटो गाली सुनने के लिये लगवा रखी है?, वित्त मंत्री अरूण जेटली की किंग फ़िशर के मालिक विजय माल्या से मुलाकात पर 'जब वी मेट-ये दुनिया वाले! पूछेंगे! मुलाकात हुई, क्या बात हुई' तथा मोदीजी के स्वच्छता अभियान पर 'स्वच्छता टैक्स मोदी को दो और सफ़ाई खुद करो' कार्टूनो द्वारा मोदी सरकार की नीतियों पर सटीक तंज कसा गया है।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता